भारत का संघ

बनाम

मैसर्स क्राफ्टर्स इंजीनियरिंग एंड लीजिंग (प्रा.) लिमिटेड

(दीवानी अपील सं. 2007/2005)

12 जुलाई, 2011

[पी. सतशिवम एवम् ए. के. पटनायक, जे. जे.]

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 - जब अनुबंध इसे प्रतिबंधित करता है तो ब्याज देने के लिए मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र - **अभिनिर्धारित किया** : ऐसे मामले में, मध्यस्थ अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि पर ब्याज नहीं दे सकता है, हालाँकि, जहां ब्याज देने के संबंध में कोई निषेध नहीं है, मध्यस्थ के पास प्रकरण के लम्बित रहने के दौरान ब्याज देने का अधिकार है। तथ्यों पर, अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि पर ब्याज के भुगतान पर रोक लगाने वाले पक्षों के बीच अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 1.15 के तहत रोक पूर्ण है और अनुबंध को दोबारा लिखे बिना ब्याज नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार, अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि के संबंध में ब्याज देने वाले मध्यस्थ के फैसले को अपास्त किया जाता है।

प्रतिवादी को एक कार्य अनुबंध से पर दिया गया था। पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए। प्रतिवादी के आवेदन पर, एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया था, लेकिन चूंकि मध्यस्थ समय सीमा के भीतर मामले पर विचार-विमर्श नहीं कर सका, इसलिए प्रतिवादी ने न्यायाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया। न्यायाध्यक्ष ने कुछ दावों के लिए पंचाट दिया और कुछ दावों को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने ब्याज देने के संबंध में

न्यायाध्यक्ष द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता याचिका और अपील को भी खारिज कर दिया।

विचाराधीन अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या मध्यस्थ के पास समझौते में ऐसा नही होने के बावजूद ब्याज देने का अधिकार क्षेत्र है।

न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति प्रदान की गई अभिनिर्धारित: 1.1 जहां पार्टियां इस बात पर सहमत हुई थीं कि कोई ब्याज देय नहीं होगा, मध्यस्थ अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि के लिए ब्याज नहीं दे सकता है। जहां पार्टियों के बीच समझौता ब्याज देने पर रोक नहीं लगाता है और जहां कोई पार्टी ब्याज का दावा करती है और उक्त विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जाता है, तो उसके पास लंबित ब्याज देने की शक्ति होगी। ऐसी स्थिति में, यह माना जाना चाहिए कि. ब्याज पार्टियों के बीच समझौते की एक निहित शर्त थी। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में, मध्यस्थ को आवश्यक रूप से प्रकरण के विचाराधीन रहने पर ब्याज देना चाहिए। ऐसे किसी भी ब्याज का दावा करने या मांग करने पर अनुबंध में किसी विशिष्ट शर्त या निषेध के अभाव में, मध्यस्थ ब्याज देने के लिए स्वतंत्र है। [पैरा 14] [210-जी-एच; 211-ए-बी]

1.2 उपर्युक्त सिद्धांत के प्रकाश में और पार्टियों के बीच अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 1.15 को ध्यान में रखते हुए, जिसके तहत यह अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि पर ब्याज के भुगतान पर रोक लगाता है, मध्यस्थ के पास ब्याज देने की शक्ति समाप्त हो जाती है। . यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 में ब्याज देने के लिए मध्यस्थ की शक्ति से संबंधित कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। हालाँकि, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में, मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान है। खंड 1.15 के तहत रोक पूर्ण है और अनुबंध को

दोबारा लिखे बिना ब्याज नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार, अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि के संबंध में ब्याज देने वाले मध्यस्थ के फैसले के साथ-साथ इसकी पुष्टि करने वाले एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। [पैरा 15 और 16] [211-सी-ई]

सचिव, सिंचाई विभाग, उड़ीसा सरकार एवम् अन्य बनाम जी. सी. रॉय (1992) 1 एससीसी 508: 1991 (3) पूरक

उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट 417; कार्यकारी अभियंता, ढेंकनाल लघु सिंचाई प्रभाग, उड़ीसा और अन्य। बनाम एन. सी. बुधराज (मृतक), द्वारा विधिक प्रतिनिधि व अन्य (2001) 2 एससीसी 721: 2001 (1) एस. सी. आर. 264; सईद अहमद और कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2009) 12 एससीसी 26: 2009 (10) एस. सी. आर. 841; श्री कामची अम्मान निर्माण बनाम मंडल रेल प्रबंधक

(निर्माण), पालघाट और अन्य (2010) 8 एससीसी 767: 2010 (10) एस. सी. आर. 487 का अवलम्ब लिया गया।

पोर्ट ऑफ कलकत्ता न्यासी मंडल बनाम इंजीनियर-डी-स्पेस एज (1996) 1 एस. सी. सी. 516: 1995 (6) पूरक एससीआर 327; मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य। (2010) 1 एससीसी 549: 2009 (16) उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट 216; भारत संघ बनाम सारस्वत व्यापार एजेंसी और अन्य। (2009) 16 एससीसी 504: 2009 (10) एस. सी. आर. 1063- का उल्लेख किया गया।

न्यायिक द्रष्टांत :

2009 (10) उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट 841 का अवलम्ब लिया गया पैरा 10

1995 (6) पूरक उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट 327 का उल्लेख किया गया पैरा 10,14

2009 (10) उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट 1063 का उल्लेख किया गया पैरा 11

2010 (10) उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट 487 का उल्लेख किया गया पैरा 13

2009 (16) उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट 216 का उल्लेख किया गया पैरा 14

1991 (3) पूरक उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट 417 का अवलम्ब लिया गया पैरा 14

2001(1) उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट 264 का अवलम्ब लिया गया पैरा 14

सिविल अपीलीय न्यायक्षेत्र सिविल अपील सं- 2005/2007

याचिका संख्या 274/2005 की अपील संख्या 219/2006 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 24.4.2006 से निर्दिष्ट

अपीलार्थी की ओर से : ए. एस. चांधियोक, ए. एस. जी., सोनिया माथुर, रितेश कुमार, पीयूष सांही, डी. एस. माहरा

प्रत्यर्थी की ओर से : रमेश बाबू, एम. आर. अरुण फ्रांसिस, जी. प्रकाश, अमरजीत सिंह बेदी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया : पी. सदाशिवम, न्यायाधिपति

1) भारत संघ की यह अपील 2006 की मध्यस्थता याचिका संख्या 274 में 2005 की अपील संख्या 219 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 24.04.2006 से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी.

2) मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के इगतपुरी-भुसावल खंड पर "सी" श्रेणी के स्टेशनों और भुसावल-बडनेरा खंड पर 2 "सी" स्टेशनों पर सिग्नलिंग व्यवस्था के कार्य के लिए रु. 18,10,400/- की लागत पर दिनांक 16.05.1988 को प्रितवादी को ठेका दिया गया। अनुबंध पूरा होने पर, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष 1993 में मुकदमा संख्या 2822 दायर करके कुछ विवाद/दावे उठाए और मध्यस्थता के माध्यम से निर्णय की मांग की। उच्च न्यायालय ने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक मध्यस्थ नियुक्त करने और विवादों को निर्णय के लिए भेजने का निर्देश दिया।चूँकि नियुक्त मध्यस्थ समय सीमा के भीतर मामले पर विचार-विमर्श नहीं कर सका, इसलिए प्रतिवादी ने न्यायाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया।न्यायाध्यक्ष ने दिनांक 26.04.2005 के आदेश से दावा संख्या 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 के लिए अवार्ड दिया और दावा संख्या 2, 5, 7 और 14 को खारिज कर दिया और उल्लेख किया कि दावा संख्या 4 के विरुद्ध सुरक्षा जमा की बैंक गारंटी वापस की जाती है।

बी) दावा संख्या 11 और 13 के लिए न्यायाध्यक्ष द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2005 की मध्यस्थता याचिका संख्या 274 दायर की। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 06.12.2005 के आदेश द्वारा उनकी याचिका खारिज कर दी।

सी) विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष 2006 की मध्यस्थता अपील संख्या 219 दायर की। डिविजन बेंच ने दिनांक 24.04.2006 के आक्षेपित आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, भारत संघ ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की ।

3) भारत संघ के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एएस चांडियोक और प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री रमेश बाबू एमआर को सुना।

4) उच्च न्यायालय के साथ-साथ हमारे समक्ष, अपीलकर्ता ने अपना मामला केवल उस ब्याज के संबंध में पेश किया जो मध्यस्थ द्वारा दिया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया, इसलिए इस अपील में विचार करने का एकमात्र बिंदु यह है कि क्या मध्यस्थ के पास समझौते में ऐसा न होने के बावजूद ब्याज देने का अधिकार क्षेत्र है?

5) हालांकि अपीलकर्ता ने दावा संख्या 11 और 13 के संबंध में न्यायाध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी है, वे मुख्य रूप से ब्याज देने के बारे में हैं; इसलिए हमारे द्वारा सभी तथ्यों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान एएसजी श्री एएस चंडियोक के अनुसार, पार्टियों के बीच अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 1.15 के मद्देनजर, मध्यस्थ के पास प्रकरण के विचाराधीन रहने पर ब्याज देने की शक्ति नहीं है। उक्त खंड इस प्रकार है:

"1.15 राशियों पर ब्याज - बयाना राशि या सुरक्षा जमा या अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, लेकिन खंड 1.14.4 के अनुसार जमा की गई सरकारी प्रतिभूतियां उस पर अर्जित ब्याज के साथ चुकानी होंगी।"

विद्वान एएसजी के अनुसार, उपर्युक्त खंड के मद्देनजर, अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है। दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रमेश बाबू एमआर ने कहा कि अनुबंध में किसी भी बाधा के बावजूद मध्यस्थ के पास ब्याज देने की शक्ति है, जिसके लिए उन्होंने बंदरगाह न्यासी मंडल कलकत्ता बनाम इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज में इस न्यायालय के निर्णय, (1996) 1 एससीसी 516 और मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य , (2010) 1 एससीसी 549 पर भरोसा किया है।

6) हमने पहले ही प्रासंगिक खंड निकाल लिया है जिसमें "अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि" शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि मध्यस्थता समझौते में अनुबंध के तहत देय राशि पर ब्याज के दावे पर विचार करने के लिए मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए कोई निषेध नहीं है, तो मध्यस्थ अवधि के संबंध में ब्याज पर विचार करने और देने के लिए स्वतंत्र है । यदि समझौते में ब्याज का भुगतान करने पर रोक है, तो उस स्थिति में, मध्यस्थ ब्याज नहीं दे सकता है। खंड 1.15 अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि पर ब्याज के भुगतान पर रोक लगाता है।

मध्यस्थता अधिनियम , 1940 के प्रावधान ही मौजूदा मामले पर लागू होते हैं। अब ब्याज अनुदान के समझौते में इसी तरह के निषेध से संबंधित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करें। सचिव, सिंचाई विभाग, उड़ीसा सरकार और अन्य बनाम जीसी रॉय , (1992) 1 एससीसी 508 में, संविधान पीठ ने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 29 पर विचार किया था जो लंबित ब्याज से संबंधित है। अधिनियम की योजना और विभिन्न पूर्व निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद, संविधान पीठ ने उसी मुद्दे पर विचार किया, अर्थात्, क्या एक मध्यस्थ के पास पेंडेंट लाइट पर

ब्याज देने की शक्ति है और यदि हां, तो किस सिद्धांत पर। प्रासंगिक पैराग्राफ यहां दिए गए हैं: -

"43. प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि क्या मध्यस्थ के पास लंबित ब्याज देने की शक्ति है, और यदि हां तो किस सिद्धांत पर। हमें दोहराना चाहिए कि हम उस स्थिति से निपट रहे हैं जहां समझौता इस तरह के ब्याज देने का प्रावधान नहीं करता है और न ही इसे प्रतिबंधित करता है। दूसरे शब्दों में, हम एक ऐसे मामले से निपट रहे हैं जहां समझौते ब्याज देने के बारे में मौन है। उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:

(i) जिस व्यक्ति को उस धन का उपयोग करने से वंचित किया गया है जिसका वह वैध रूप से हकदार है, उसे उस अभाव के लिए मुआवजा पाने का अधिकार है, इसे किसी भी नाम से पुकारें। इसे ब्याज, मुआवज़ा या हर्जाना कहा जा सकता है। यह मूल विचार उस अवधि के लिए ही मान्य है जब विवाद मध्यस्थ के समक्ष लंबित है, जितना मध्यस्थ द्वारा संदर्भ में प्रवेश करने से पहले की अवधि के लिए है। यह धारा 34 , सिविल प्रक्रिया संहिता का सिद्धांत है और मध्यस्थ के मामले में अन्यथा मानने का कोई कारण या सिद्धांत नहीं है।

(ii) पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थ एक वैकल्पिक फोरम (एसआईसी फोरम) है। यदि ऐसा है, तो उसके पास पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों या मतभेदों को तय करने की शक्ति होनी चाहिए। यदि मध्यस्थ के पास पेंडेंट लाइट पर ब्याज देने की कोई शक्ति नहीं है, तो दावा करने वाले पक्ष को उस उद्देश्य के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा, भले ही उसने

मध्यस्थ से अन्य दावों के संबंध में संतुष्टि प्राप्त कर ली हो। इससे कार्यवाही की बहुलता हो जाएगी।

(iii) एक मध्यस्थ एक समझौते का निर्माता है। यह पार्टियों के लिए खुला है कि वे उसे ऐसी शक्तियाँ प्रदान करें और उसके पालन के लिए ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करें, जैसा कि वे उचित समझें, जब तक कि वे कानून का विरोध न करें। (मध्यस्थता अधिनियम की धारा 41 और धारा 3 का प्रावधान इस बिंदु को स्पष्ट करता है)। फिर भी, समझौता कानून के अनुरूप होना चाहिए। मध्यस्थ को भी देश के सामान्य कानून और समझौते के अनुसार कार्य करना चाहिए और अपना निर्णय देना चाहिए।

(iv) वर्षों से, अंग्रेजी और भारतीय अदालतों ने इस धारणा पर काम किया है कि जहां समझौता निषेध नहीं करता है और एक पक्ष ब्याज के लिए दावा करता है, मध्यस्थ के पास लंबित ब्याज देने की शक्ति होनी चाहिए। इस न्यायालय के बाद के निर्णयों में थावरदास का पालन नहीं किया गया है। इसे इस आधार पर स्पष्ट और अलग किया गया है कि उस मामले में ब्याज के लिए कोई दावा नहीं था, बल्कि केवल अनिश्चित क्षति के लिए दावा था। यह बार-बार कहा गया है कि उक्त निर्णय की टिप्पणियों का उद्देश्य ऐसा कोई पूर्ण या सार्वभौमिक नियम निर्धारित करना नहीं था जैसा कि पहली नज़र में लगता है। जेना मामले तक देश की लगभग सभी अदालतों ने ब्याज पेंडेंट लाइट का फैसला देने की मध्यस्थ की शक्ति को बरकरार रखा था। निरंतरता और निश्चितता कानून की अत्यंत वांछनीय विशेषता है।

(v) लंबित ब्याज तात्विक कानून का मामला नहीं है, जैसे संदर्भ से पहले की अवधि के लिए ब्याज (पूर्व-संदर्भ अवधि)। पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए सदैव ऐसी शक्ति का अनुमान लगाया गया है।

44. उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, हम सोचते हैं कि निम्नलिखित सही सिद्धांत है जिसका इस संबंध में पालन किया जाना चाहिए:

जहां पार्टियों के बीच समझौता ब्याज देने पर रोक नहीं लगाता है और जहां एक पार्टी ब्याज का दावा करती है और वह विवाद (मूल राशि के दावे के साथ या स्वतंत्र रूप से) मध्यस्थ को भेजा जाता है, उसके पास लंबित ब्याज देने की शक्ति होगी। ऐसा इस कारण से है कि ऐसे मामले में यह माना जाना चाहिए कि ब्याज पार्टियों के बीच समझौते का एक निहित शर्त थी और इसलिए जब पार्टियां अपने सभी विवादों को संदर्भित करती हैं - या विवाद को ब्याज के रूप में संदर्भित करती हैं - मध्यस्थ के पास ब्याज देने की शक्ति होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक मामले में मध्यस्थ को आवश्यक रूप से लंबित ब्याज दिलाया जाना चाहिए। यह उसके विवेक का मामला है कि न्याय के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में इसका प्रयोग किया जाए।"

8) कार्यकारी अभियंता, ढेंकनाल लघु सिंचाई प्रभाग, उड़ीसा और अन्य बनाम एनसी बुधराज (मृतक) द्वारा एलआर और अन्य, (2001) 2 एससीसी 721 में, एक अन्य संविधान पीठ ने ब्याज उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में पूर्व-संदर्भ अवधि के लिए ब्याज के भुगतान पर विचार किया। जब ब्याज अधिनियम , 1839 लागू था। पैरा 26 में निम्नलिखित निष्कर्ष प्रासंगिक है जो इस प्रकार है:

"26. ऊपर बताए गए सभी कारणों के लिए, हम यह मानते हुए संदर्भ का उत्तर देते हैं कि अदालत के हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना नियुक्त मध्यस्थ के पास पूर्व-संदर्भ अवधि के लिए देय और देय राशि पर ब्याज देने का अधिकार क्षेत्र है, ऐसे किसी भी ब्याज का दावा करने या अनुदान देने के लिए अनुबंध में किसी विशिष्ट शर्त या निषेध

के अभाव में। जेना मामले में एक विपरीत दृष्टिकोण लेने वाला निर्णय सही स्थिति नहीं देता है और Over Ruled का दिया गया है, जिसका अर्थ है कि यह निर्णय किसी भी पक्ष को न ही यह किसी अदालत को उन कार्यवाही को फिर से खोलने का अधिकार देता है, जो पहले ही अंतिम हो चुकी हैं, और केवल किसी भी लंबित कार्यवाही पर लागू होती हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है।

9) पहले के पैराग्राफ में, हमने प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील द्वारा अपनाए गए रुख और कलकत्ता बंदरगाह न्यासी बोर्ड (सुप्रा) में रिपोर्ट किए गए निर्णय के आधार पर निर्भरता का उल्लेख किया है। यह सच है कि उस फैसले में, इस न्यायालय ने माना है कि मध्यस्थ के पास अनुबंध की धाराओं की व्याख्या करने और यह तय करने का अधिकार क्षेत्र है कि क्या उसके द्वारा लंबित ब्याज दिया जा सकता है। उस मामले में जो संक्षिप्त प्रश्न उठा वह यह था कि मध्यस्थ ने विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के खिलाफ अनुबंध में निहित निषेध के बावजूद ब्याज पेंडेंट लाइट का दिलाया था। अंततः, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला है कि अनुबंध की शर्तों के बावजूद, मध्यस्थ ब्याज का फैसला देने में अपने अधिकार क्षेत्र में था। यह इंगित करना उपयोगी है कि उस निर्णय में अनुपात पर इस न्यायालय द्वारा सईद अहमद एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य , (2009) 12 एससीसी 26 में विचार किया गया था। उसी मुद्दे पर विचार करते समय, विशेष रूप से, विशिष्ट खंड में ब्याज पेंडेंट लाइट पर रोक लगाने वाले समझौते पर, इस न्यायालय ने उसी निर्णय यानी कलकत्ता बंदरगाह न्यासी बोर्ड (सुप्रा) पर विचार किया। कलकत्ता बंदरगाह के बोर्ड (सुप्रा) और जीसी रॉय के मामले (सुप्रा) में संविधान पीठ ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:

"23. इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज में अवलोकन से अनुबंध की अवधि केवल विभाग/नियोक्ता को विलंबित भुगतान के लिए ठेकेदार को ब्याज का भुगतान करने से रोकती है, लेकिन एक बार मामला मध्यस्थ के पास चला जाता है, तो मध्यस्थ का विवेक नहीं होता है अनुबंध की शर्तों से किसी भी तरह से बाधित होने पर और मध्यस्थ ब्याज लंबित मामले पर विचार करने और देने का हकदार होगा, इसका उपयोग एक अजीब तर्क का समर्थन करने के लिए नहीं किया जा सकता है कि सरकार या विभाग पर ब्याज का भुगतान करने पर रोक मध्यस्थ द्वारा ब्याज दिए जाने पर रोक है । क्या अनुबंध में प्रावधान नियोक्ता को ब्याज के लिए किसी भी दावे पर विचार करने से रोकता है या ठेकेदार को ब्याज के लिए कोई दावा करने से रोकता है, यह ब्याज के संबंध में एक स्पष्ट निषेध है। प्रावधान में मध्यस्थ को ब्याज देने से रोकने के लिए कोई अन्य रोक शामिल नहीं होनी चाहिए .ब्याज पेंडेंट लाइट के ब्याज के संदर्भ में की गई टिप्पणियों का उपयोग अनुबंध से बाहर नहीं किया जा सकता है।

24. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज में उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर अगली दलील दी कि भले ही खंड G1.09 पूर्व-संदर्भ अवधि में ब्याज पर रोक लगाने के लिए है, लेकिन इसे पेंडेंट लाइट अवधि यानी 14-3-1997 से 31-7-2001 तक की अवधि के लिए नही माना जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि संदर्भ के लंबित रहने के दौरान ब्याज का फैसला मध्यस्थ के विवेक के अंतर्गत था और इसलिए, उस अवधि के लिए ब्याज के फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज में फैसले से पहले और बाद में जीसी रॉय और एनसी बुद्धराज में दिए गए संविधान पीठ के फैसलों को देखते हुए, यह संदिग्ध है कि क्या मध्यस्थता अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मामले में इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज का अवलोकन किया गया है । , 1940 कि मध्यस्थ अनुबंध में एक्सप्रेस बार की अनदेखी करते हुए, लंबित ब्याज का फैसला दे सकता है, यह अच्छा कानून है। लेकिन

इस पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह नए अधिनियम के तहत एक मामला है जहां मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान है।"

10) संविधान पीठ द्वारा चर्चा और व्याख्या के अनुसार समझौते में विशिष्ट निषेध को ध्यान में रखते हुए, हम सईद अहमद एंड कंपनी (सुप्रा) में व्यक्त विचार के साथ सम्मानजनक समझौते में हैं और हम संभवतः पोर्ट न्यासी बोर्ड में लिए गए निष्कर्ष से सहमत नहीं हो सकते हैं। कलकत्ता (सुप्रा) में मध्यस्थता अधिनियम , 1940 के तहत उत्पन्न होने वाले एक मामले में मध्यस्थ अनुबंध में एक्सप्रेस बार की अनदेखी करते हुए ब्याज पेंडेंट लाइट पर दिया जा सकता है।

11) भारत संघ बनाम सारस्वत ट्रेडिंग एजेंसी और अन्य , (2009) 16 एससीसी 504 में, हालांकि यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम , 1996 के तहत था, इस न्यायालय ने सभी का उल्लेख करते हुए बाद ब्याज के संबंध में कानूनी स्थिति के बारे में विस्तार से विचार किया है। पहले के फैसले और समझौते के खंड 31 पर निर्भरता को आधार बनाते हुए कहा गया: "33। मौजूदा मामले में समझौते का खंड 31 भौतिक रूप से अलग है। यह किसी भी कारण से ठेकेदार को किसी भी ब्याज या क्षति के भुगतान पर रोक लगाता है, इसलिए, स्पष्ट रूप से यह विचार है कि आइटम 3 के तहत राशि पर प्रतिवादी को कोई प्री-रेफरेंस या पेंडेंट लाइट ब्याज देय नहीं था और उस राशि पर प्री-रेफरेंस और पेंडेंट लाइट ब्याज की अनुमति देने वाला मध्यस्थ का फैसला स्पष्ट रूप से व्यक्त शर्तों का उल्लंघन था। जहां तक आइटम 3 के तहत राशि पर पूर्व-संदर्भ और लंबित ब्याज का संबंध है, उच्च न्यायालय का आदेश अस्थिर है।"

12) बहस के अंत में, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय के हालिया फैसले पर बहुत अधिक भरोसा

किया, जो मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत उत्पन्न हुआ था। वहां भी, एससीसी के खंड 30 और खंड जीसीसी का 52 ब्याज के भुगतान पर रोक लगाता है। हालाँकि बेंच ने पहले के सभी निर्णयों पर भरोसा किया और उसी खंड पर विचार किया जिस पर हम अब चर्चा कर रहे हैं, समझौते में विशिष्ट रोक के लिए मध्यस्थ डी होर्स द्वारा ब्याज देने के आदेश को बरकरार रखा। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के फैसले को श्री कामची अम्मन कंस्ट्रक्शन बनाम डिवीजनल रेलवे मैनेजर (वर्क्स), पालघाट और अन्य, (2010) 8 एससीसी 767 मामले में इस न्यायालय की एक अन्य पीठ के समक्ष उद्धृत किया गया था। जिसमें मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में लिए गए फैसले पर काफी चर्चा और विचार किया गया। संविधान पीठ के फैसलों सहित पहले के सभी फैसलों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के प्रभाव का विश्लेषण किया है। निम्नलिखित चर्चा और अंतिम निष्कर्ष प्रासंगिक हैं:

"17. मदनानी में मध्यस्थ ने मध्यस्थ की नियुक्ति की तारीख से फैसले की तारीख तक, यानी लंबित ब्याज का फैसला सुनाया था। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर इसमें हस्तक्षेप किया था कि अनुबंध में ब्याज दिलाए जाने पर एक विशिष्ट निषेध था। इस न्यायालय ने इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज में निर्णय के बाद उक्त अस्वीकृति को उलट दिया और निम्नानुसार माना:

(मदनानी मामला, एससीसी पृ. 560-61, पैरा 39)

"39. वर्तमान मामले में भी प्रासंगिक खंड, जो ऊपर उद्धृत किए गए हैं, अर्थात्, जीसीसी के खंड 16(2) और एससीसी के खंड 30 में मध्यस्थ पर ब्याज देने पर कोई

प्रतिबंध नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय का उपरोक्त खंडों के आधार पर मामले पर मध्यस्थ के फैसले में हस्तक्षेप करना सही नहीं था।इसलिए हम उन खंडों के सख्त तथ्यों पर और इंजीनियरों में अनुपात पर भरोसा करते हुए पाते हैं कि उक्त खंड किसी भी तरह की मध्यस्थ को ब्याज देने में कोई बाधा नहीं डालते हैं।"

18. सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज और मदनानी पुराने मध्यस्थता अधिनियम , 1940 के तहत उत्पन्न हुए थे जिसमें नए अधिनियम की धारा 31(7) के समान कोई प्रावधान नहीं था। सईद अहमद मामले में इस न्यायालय ने माना कि पुराने अधिनियम के तहत दिए गए निर्णय नए अधिनियम के तहत ब्याज अनुदान की वैधता तय करने में सहायक नहीं हो सकते हैं। इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज में तर्क था कि अनुबंध कार्रवाई के कारण की तारीख से संदर्भ की तारीख तक ब्याज को नियंत्रित करता था, मध्यस्थ के पास संदर्भ की तारीख से देने की तारीख तक ब्याज की दर तय करने का विवेक था। और जहां तक लंबित अवधि की बात है, वह अनुबंध में निहित ब्याज के संबंध में किसी भी निषेध से बाध्य नहीं था। सईद अहमद मामले में इस अदालत ने माना कि इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज में निर्णय नए अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों पर लागू नहीं होगा। हम नीचे, सईद अहमद से प्रासंगिक अंश निकालते हैं: (एससीसी पृष्ठ 36, पैरा 23-24) "23। इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज के अवलोकन से अनुबंध की अवधि केवल विभाग/नियोक्ता को ब्याज का भुगतान करने से रोकती है विलंबित भुगतान के लिए ठेकेदार को, लेकिन एक बार मामला मध्यस्थ के पास चला जाता है, तो मध्यस्थ का विवेक किसी भी तरह से अनुबंध की शर्तों से प्रभावित नहीं होता है और मध्यस्थ लंबित ब्याज पर विचार करने और दिलाए जाने का हकदार होगा। एक विचित्र तर्क का समर्थन करने के लिए कि सरकार या विभाग पर ब्याज का भुगतान करने से रोकना, मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने

पर रोक नहीं है। क्या अनुबंध में प्रावधान नियोक्ता को ब्याज के लिए किसी भी दावे पर विचार करने से रोकता है या ठेकेदार को ब्याज के लिए कोई भी दावा करने से रोकता है, यह ब्याज के संबंध में एक स्पष्ट निषेध के समान है। प्रावधान में मध्यस्थ को ब्याज देने से रोकने के लिए किसी अन्य रोक की आवश्यकता नहीं है। ब्याज पेंडेंट लाइट के संदर्भ में की गई टिप्पणियों का उपयोग अनुबंध से बाहर नहीं किया जा सकता है।

24. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज में उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर अगली दलील दी कि भले ही क्लॉज जी 1.09 को पूर्व-संदर्भ अवधि में ब्याज पर रोक लगाने के लिए माना जाता है, लेकिन इसे नहीं माना जाना चाहिए पेंडेंट लाइट अवधि, यानी 14-3-1997 से 31-7-2001 तक। उन्होंने तर्क दिया कि संदर्भ के लंबित रहने के दौरान ब्याज का फैसला मध्यस्थ के विवेक के अंतर्गत था और इसलिए, उस अवधि के लिए ब्याज के फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज में फैसले से पहले और बाद में जीसी रॉय और एनसी बुद्धराज में दिए गए संविधान पीठ के फैसलों को देखते हुए, यह संदिग्ध है कि क्या मध्यस्थता अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मामले में इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज का अवलोकन किया गया है । 1940 मध्यस्थ अनुबंध में एक्सप्रेस बार की अनदेखी करते हुए मध्यस्थ लंबित ब्याज का फैसला दे सकता है, यह अच्छा कानून है। लेकिन इस पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह नए अधिनियम के तहत मामला है जहां मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान है।"

यही तर्क मदनानी के फैसले पर भी लागू होता है क्योंकि वह भी पुराने अधिनियम के तहत एक मामले से संबंधित है और इस मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया गया है बल्कि केवल इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज के फैसले पर भरोसा किया है।

19. नए अधिनियम की धारा 37(1) शब्दों का उपयोग कि "जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि मध्यस्थ अनुबंध की शर्तों से बंधा हुआ है जहां तक कि कार्रवाई की तारीख से अदायगी तक ब्याज दिया जा सकता है, इसलिए, जहां पार्टियां इस बात पर सहमत हुई थीं कि कोई ब्याज देय नहीं होगा, मध्यस्थता न्यायाधिकरण उस तारीख के बीच का ब्याज नहीं दे सकता जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ तथा अदायगी का आदेश हुआ।

20. हमारे विचार में इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज और मदनानी के निर्णय एक अन्य कारण से लागू नहीं होते हैं। इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज और मदनानी में मध्यस्थ ने पेंडेंट लाइट अवधि के लिए ब्याज दिया था। इस न्यायालय ने पुराने अधिनियम के तहत इस तरह के ब्याज के फैसले को इस आधार पर बरकरार रखा कि मध्यस्थ के पास यह तय करने का विवेक था कि लंबित अवधि के दौरान ब्याज दिया जाना चाहिए या नहीं और वह ब्याज के मामले में अनुबंध की शर्तों से बंधा नहीं था। लेकिन मौजूदा मामले में मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने लंबित अवधि के लिए ब्याज देने से इनकार कर दिया है। जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने विवेक का प्रयोग किया है और लंबित अवधि के लिए ब्याज देने से इनकार कर दिया है, भले ही उन दो मामलों में सिद्धांत लागू हों, मध्यस्थ के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर भी इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज और मदनानी के फैसले लागू नहीं होते..."

13) जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमने पहले ही इसी तरह का विचार व्यक्त किया है और मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में तर्क को लागू करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है, हम श्री कामची अम्मन कंस्ट्रक्शन (सुप्रा) में व्यक्त किए गए विचार का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

14) उपरोक्त चर्चा के आलोक में निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है:

कलकत्ता बंदरगाह (सुप्रा) न्यासी बोर्ड में अनुपात पर आधारित निर्भरता अस्वीकार्य है क्योंकि सईद अहमद एंड कंपनी (सुप्रा) में उक्त दृष्टिकोण को खारिज कर दिया गया है और जहां तक मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में अनुपात का सवाल है यह पहले के पैराग्राफ में उल्लिखित कारणों से भी अस्वीकार्य है, हम प्रतिवादी के वकील द्वारा अपनाए गए रुख को अस्वीकार करते हैं। दूसरी ओर, हम भारतीय संघ के रुख को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं जैसा कि विद्वान एएसजी श्री एएस चंडियोक ने सही ढंग से पेश किया है। हम दोहराते हैं कि जहां पार्टियां इस बात पर सहमत हुई थीं कि कोई ब्याज देय नहीं होगा, मध्यस्थ अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि के लिए ब्याज नहीं दे सकता है। जहां पार्टियों के बीच समझौता ब्याज देने पर रोक नहीं लगाता है और जहां कोई पार्टी ब्याज का दावा करती है और उक्त विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जाता है, तो उसके पास लंबित ब्याज देने की शक्ति होगी। जैसा कि जीसी रॉय के मामले (सुप्रा) में संविधान पीठ ने देखा, ऐसे मामले में, यह माना जाना चाहिए कि ब्याज पार्टियों के बीच समझौते का एक निहित शर्त थी। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में, मध्यस्थ को आवश्यक रूप से पेंडेंट लाइट पर ब्याज देना चाहिए। संविधान पीठ के बाद के फैसले में, यानी, एनसी बुद्धराज के मामले (सुप्रा) में, यह दोहराया गया है कि इस तरह के किसी भी ब्याज का दावा करने या अदायगी का आदेश देने के लिए अनुबंध में किसी विशिष्ट शर्त या निषेध के अभाव में, मध्यस्थ ब्याज देने के लिए स्वतंत्र है।

15) उपरोक्त सिद्धांत के आलोक में और खंड 1.15 में निहित अनुबंध के विशिष्ट निषेध को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थ के पास ब्याज देने की शक्ति समाप्त हो जाती है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि मध्यस्थता अधिनियम , 1940 में ब्याज देने के लिए

मध्यस्थ की शक्ति से संबंधित कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। हालाँकि, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम , 1996 में, मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान है। खंड 1.15 के तहत रोक पूर्ण है और अनुबंध को दोबारा लिखे बिना ब्याज नहीं दिया जा सकता है।

16) उपरोक्त कारणों से, हम अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि के संबंध में ब्याज देने वाले मध्यस्थ के फैसले को जिसकी पुष्टि विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा की गई, को अपास्त करते है।

17) परिणामतः उपर जो बिन्दु अवधारित किए गए हैं, के अनुसार अपील स्वीकार की जाती है।खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सतीश चंद (आर.जे.एस.) जिला एवम् सेशन न्यायाधीश धौलपुर (राजस्थान) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।